GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 17 Jan, 2025

Edition: International

Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग को अंजाम दिया, जिससे भारत को अंतरिक्ष के शीर्ष क्लब में शामिल किया गया
Page 03 **Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	श्रीहरिकोटा को तीसरा लॉन्च पैड मिलेगा
Page 04 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	केंद्र ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की
Page 04 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली; शीर्ष न्यायालय में पूर्ण क्षमता के करीब
समाचार में	गाजा में चरणबद्ध युद्धविराम
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	भारत के साथ लोकतांत्रिक गठबंधन इसके मूल में है

GEO IAS It's about quality

Page 01 : GS 3 : Science and Technology

इसरो ने स्पैडेक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिससे भारत के अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला।

ISRO executes satellite docking, places India in elite space club

SpaDeX mission gained control of two satellites as a single object; space agency to follow up manoeuvre with undocking and power transfer checks in coming days; India joins the ranks of the U.S., Russia and China to achieve the historic feat

Hemanth C.S.
BENGALURU

The Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully executed a satellite docking experiment in the early hours of Thursday, "making India the fourth country" after the U.S., Russia and China to achieve this historic feat.

The two satellites – SDX01 (Chaser) and SDX02 (Target) – launched by the PSLV C60 on December 30 successfully docked as officials from the Mission Operations Complex (MOX) at the ISRO Telemetry, Tracking, and Command Network (ISTRAC) oversaw the complex procedure.

"Docking Success Spacecraft docking successfully completed! A historic moment. Let's walk through the SpaDeX docking process: Manoeuvre from 15m to 3m hold point completed. Docking initiated with precision, leading to successful spacecraft capture. Retraction completed smoothly, followed by rigidisation for stability. Docking successfully completed. India became the 4th country to achieve successful Space Docking. Congratulations to the entire team! Congratulations to India!," ISRO said on X.

Post-docking, the agency took control of the two satellites as a single object. "Undocking and power transfer checks to follow in coming days," it added.

The SpaDeX mission is an important project designed to develop and demonstrate the technology needed for spacecraft manoeuvres. The demonstration of this technology is essential for futuristic missions such as sending an Indian astronaut to the moon, sample return from the moon, and building and operating an Indian space station.

The other objectives of the mission include demonstration of the transfer of electric power between the docked spacecraft, which is essential for future applications such as in-space robotics, composite spacecraft control and payload operations after undocking.

According to ISRO, after the docking and undocking events, the spacecraft will be separated and used for application missions.

"After successful docking and rigidization, electrical power transfer between the two satellites will be demonstrated before undocking and separation of the two satellites to start the operation of their respective payloads for the expected mission life of up to two years," ISRO said.

The SpaDeX docking was scheduled on January 7 but was postponed. "The docking process requires further validation through ground simulations based on an abort scenario identified today (January 6)," ISRO had cited as reason.

On January 8, 2025, hours before it was scheduled to carry out the SpaDeX docking experiment, ISRO said that the docking experiment had to be postponed again as the drift between the satellites was more than what they had expected. It later arrested the drift between the spacecraft.

ISRO launched the SpaDeX mission on December 30 from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota. A few minutes after liftoff, the two satellites (Target and Chaser) weighing about 220 kg each were launched into a 475-km circular orbit as intended.

GATES IN THE SKY
» PAGE 8

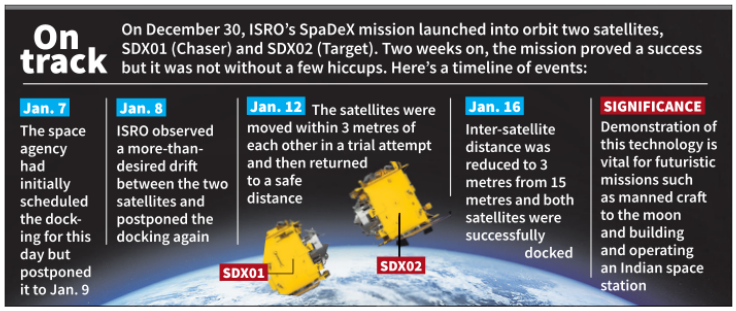

समाचार का विश्लेषण:

- **अंतरिक्ष डॉकिंग क्या है?**
  - o अंतरिक्ष डॉकिंग दो तेज़ गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाने, उन्हें एक-दूसरे के करीब लाने और अंत में उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है।
  - o यह क्षमता उन मिशनों के लिए आवश्यक है, जिनमें अंतरिक्ष स्टेशन जैसी बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करना, कक्षा में ईंधन भरना या परिक्रमा करने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर चालक दल और आपूर्ति ले जाना शामिल है।
  - o भारत का सफल डॉकिंग प्रदर्शन इसे दुनिया भर में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बनाता है, जिसने यह उपलब्धि हासिल की है, जो इसरो के तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपलब्धि का महत्व

- **यह उपलब्धि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है:**
  o अंतरिक्ष स्टेशन विकास: भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसकी योजना 2035 तक बनाई जाएगी, कक्षा में अपने मॉड्यूलर घटकों को इकट्ठा करने के लिए डॉकिंग पर निर्भर करेगा।
  o चंद्र मिशन: भारत के नियोजित चंद्र नमूना-वापसी मिशन, चंद्रयान-4 को एकत्रित नमूनों को वापस पृथ्वी पर स्थानांतरित करने के लिए डॉकिंग क्षमताओं की आवश्यकता होगी।
  o मानव अंतरिक्ष उड़ान: भविष्य के मानवयुक्त मिशन, जिनमें 2040 तक चंद्रमा पर जाने वाले मिशन भी शामिल हैं, चालक दल और उपकरणों के स्थानांतरण के लिए डॉकिंग तकनीक पर निर्भर होंगे।
- **डॉकिंग प्रयोग का विवरण**
  o इसरो ने प्रयोग के लिए दो 220 किलोग्राम के उपग्रहों, SDX01 ("चेज़र") और SDX02 ("टारगेट") का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में शामिल थे:
  1. उपग्रहों को क्रमिक रूप से करीब लाना, महत्वपूर्ण दूरी (5 किमी, 500 मीटर, 3 मीटर, आदि) पर स्थिति बनाए रखना।
  2. उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में जोड़ना और लॉक करना।
  3. एक समग्र इकाई के रूप में उपग्रहों के संयुक्त नियंत्रण और कार्यक्षमता का प्रदर्शन करना।
  o भविष्य के कदमों में उपग्रहों के बीच विद्युत शक्ति साझा करना और "अनडॉकिंग" का प्रदर्शन करना शामिल है, जहाँ उपग्रह अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं।

मिशन के दौरान आने वाली चुनौतियाँ

- शुरुआती प्रयासों के दौरान अप्रत्याशित बहाव और अशुद्धियों के कारण डॉकिंग में देरी हुई।
- इसरो ने सफल डॉकिंग के लिए आवश्यक सटीक संरेखण प्राप्त करने के लिए सिमुलेशन को परिष्कृत किया और अतिरिक्त युद्धाभ्यास किए।
- यह पुनरावृत्तीय प्रक्रिया जटिल अंतरिक्ष संचालन को संभालने में इसरो की बढ़ती विशेषज्ञता को उजागर करती है।

मुख्य प्रौद्योगिकी और नवाचार

- सेंसर: सटीक माप के लिए लेजर रेंज फाइंडर और प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर जैसे उन्नत सेंसर का उपयोग किया गया।
- नेविगेशन: सैटेलाइट नेविगेशन पर आधारित एक नए प्रोसेसर ने अंतरिक्ष यान की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित किया।
- सरलीकृत तंत्र: एंड्रोजेनस डॉकिंग सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उपयोग किए जाने वाले 24 मोटर्स की तुलना में केवल दो मोटर्स का उपयोग किया, जो नवाचार और दक्षता को दर्शाता है।

भविष्य के निहितार्थ

- **यह मिशन भारत की व्यापक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का अग्रदूत है:**
  o अंतरिक्ष स्टेशन: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूलर असेंबली के लिए इस तकनीक का उपयोग करेगा।
  o चंद्र अन्वेषण: डॉकिंग नमूना-वापसी मिशन और चंद्रमा पर संभावित मानव अभियानों के लिए केंद्रीय होगी।

- स्वायत्तता: स्वायत्त डॉकिंग सिस्टम विकसित करने से नेविगेशन डेटा पर निर्भरता कम होगी, जिससे भविष्य के मिशनों के लिए दक्षता बढ़ेगी।

निष्कर्ष

- स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति को रेखांकित करता है।
- यह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने, चंद्र नमूना वापसी मिशन संचालित करने और चंद्रमा पर मानव अन्वेषण को सक्षम करने के इसरो के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक अंतरिक्ष प्रयासों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को चिह्नित करता है।

GEO IAS
It's about quality

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में 3,984.86 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी।

Sriharikota to get third launch pad

Union Cabinet gives nod for the construction; planned with a ₹3,984.86-crore outlay and a four-year timeline, the third launch pad will serve as a 'standby' for the first two launch pads, and support newer launch vehicles developed by the ISRO

Fresh boost: The previous launch pad at Sriharikota has been operational for almost two decades. PTI

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Cabinet on Thursday approved the construction of a third launch pad at the Satish Dhawan Space Centre (SDSC) in Sriharikota, Union Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw said on Thursday.

The launch pad will have an outlay of ₹3,984.86 crore, and is targeted to be completed by early 2029.

The launch pad comes as the Indian Space Research Organisation (ISRO) seeks to launch its Next Generation Launch Vehicles (NGLVs) starting in 2031.

ISRO said in a statement that it would also support Indian-manned spaceflight missions, with its chairman V. Narayanan envisaging a 2026 target for the first such mission.

"The third launch pad is designed to have configuration that is as universal and adaptable as possible that can support not only NGLV but also the Launch Vehicle Mark 3 vehicles with semicryogenic stage as well as scaled up configurations of NGLV," a Cabinet statement said.

The previous launch pad has been operational for almost two decades, and this new pad will boost ISRO's launch capabilities and capacities in Sriharikota.

"The expeditious establishment of a third launch pad to cater to a heavier class of Next Generation Launch Vehicles and as a standby for SLP is highly essential so as to meet the evolving space transportation requirements for another 25-30 years," the Cabinet note underlined.

तीसरे लॉन्च पैड की स्वीकृति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसके लिए 3,984.86 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

योजनाबद्ध समयरेखा

- लॉन्च पैड का निर्माण 2029 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए तत्परता सुनिश्चित होगी।

अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (एनजीएलवी) की सुविधा

- तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (एनजीएलवी) के प्रक्षेपण का समर्थन करेगा, जिसे इसरो 2031 तक चालू करने की योजना बना रहा है।

- यह विकास उन्नत और भारी श्रेणी के लॉन्च वाहनों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए इसरो के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए समर्थन

- नया लॉन्च पैड भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका पहला मिशन 2026 के लिए लक्षित है, जैसा कि इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा है।

सार्वभौमिक और अनुकूलनीय डिजाइन

- तीसरे लॉन्च पैड को सार्वभौमिक और अनुकूलनीय विन्यास के साथ डिजाइन किया जा रहा है, ताकि निम्नलिखित का समर्थन किया जा सके:
- अर्ध-क्रायोजेनिक चरणों से सुसज्जित NGLV।
- लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM3) और इसके उन्नत विन्यास।
- लॉन्च व्हीकल तकनीक में भविष्य की उन्नति।

इसरो की लॉन्च क्षमताओं को बढ़ाना

- दूसरे लॉन्च पैड के लगभग दो दशकों से संचालन में होने के साथ, तीसरे लॉन्च पैड के जुड़ने से स्टैंडबाय के रूप में कार्य करेगा और भारत की लॉन्च क्षमता का विस्तार होगा, जिससे अंतरिक्ष परिवहन की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना

- यह सुविधा अगले 25-30 वर्षों के लिए भारत की अंतरिक्ष परिवहन मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो भारी श्रेणी के वाहनों और उन्नत मिशन प्रोफाइल दोनों का समर्थन करती है।

रणनीतिक महत्व

- तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने, लॉन्च मिशनों में अधिक आवृत्ति और विविधता को सक्षम करने और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

- एसडीएससी श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के लिए स्वीकृति इसरो के अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई सुविधा अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन और भविष्य की तकनीकी प्रगति का समर्थन करेगी, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति मजबूत होगी। यह परियोजना अगले 25-30 वर्षों के लिए अंतरिक्ष परिवहन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो की तत्परता सुनिश्चित करती है।

- कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों की वेतन और पेंशन संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।

आठवें वेतन आयोग की मंजूरी

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

लाभार्थी

- वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिनमें सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी शामिल हैं।
- अकेले दिल्ली में ही केंद्र सरकार के लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं।

संरचना और नियुक्ति

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में समाप्त होने वाले सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
- अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, जिसका अध्यक्ष पारंपरिक रूप से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे (जैसे, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे)।

सिफारिशों का प्रभाव

- सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन समझौते और राज्यों में इसी तरह के वेतन संशोधन के लिए आधार का काम करेंगी।
- 2016 में सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से वित्त वर्ष 2016-17 में राजकोष पर ₹1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

- इस निर्णय से उपभोग और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- यह कर्मचारी कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ट्रेड यूनियन की प्रतिक्रियाएँ

- ट्रेड यूनियनों ने इस कदम का स्वागत किया और संदर्भ की स्पष्ट शर्तों की

Centre announces constitution of Eighth Pay Commission

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Ashwini Vaishnaw

Days ahead of the Delhi Assembly election, the Union government approved the establishment of the Eighth Pay Commission here on Thursday, accepting a demand of the Central trade unions and employees' organisations.

The outcome of the new Pay Commission will benefit about 50 lakh employees and 65 lakh pensioners of the Union government, including serving and retired defence personnel. Delhi itself houses about four lakh employees of the Union government.

Talking to reporters after a Cabinet meeting, Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said Prime Minister Narendra Modi had taken the decision to constitute the Eighth Pay Commission. He said the Chairperson and two members of the commission would be appointed soon.

Usually, a retired Supreme Court judge heads the Pay Commission. The Seventh Pay Commission was headed by Justice A.K. Mathur (retd). It started functioning in 2014 and submitted its report in 2016. The new scale as recommended by the Seventh Pay Commission was implemented in November 2016, and the expenses to the exchequer for implementing it were about ₹1 lakh crore in 2016-17.

Once accepted, the Pay Commission's recommendations will be the basis for wage settlement in public sector undertakings, and similar pay revision exercises in States.

"This will provide a significant boost to consumption and economic growth, along with improved quality of life for government employees," a source in the government said.

Mr. Vaishnaw said that though the term of the Seventh Pay Commission ended only in 2026, the Prime Minister had approved the Eighth Pay Commission well ahead of time.

Trade unions said they welcomed the move, and that they would wait for the terms of reference and the constitution of the panel.

Member of the Joint Consultative Machinery between the Centre and its employees, and general secretary of the All India Defence Employees Federation C. Srikumar said that employees had been demanding for over a year that the Centre constitute the Eighth Pay Commission.

"Any Pay Commission takes minimum two years time to submit its report. Recently, Central trade unions, in their meeting with the Finance Minister, too had raised this demand," Mr. Srikumar said, adding that there should be clarity on the concepts of "living wage" and "living pension".

The Rashtriya Swayamsevak Sangh-backed trade union Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) said in a statement that the decision proved the government's commitment towards working people. The BMS hoped the panel would be constituted at the earliest.

आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से "जीवित मजदूरी" और "जीवित पेंशन" अवधारणाओं पर।

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने निर्णय की सराहना की और पैनल के शीघ्र गठन का आग्रह किया।

सिफारिशों के लिए समयसीमा

- पूर्वानुमान के अनुसार, वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आमतौर पर लगभग दो साल लगते हैं, जिससे समय पर कार्यान्वयन के लिए यह प्रारंभिक स्वीकृति महत्वपूर्ण हो जाती है।

महत्व

- आठवें वेतन आयोग की स्थापना कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करने और उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जो आर्थिक विकास में और योगदान देती है।

निष्कर्ष

- आठवें वेतन आयोग की स्वीकृति कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका समय पर गठन वेतन और पेंशन संबंधी मांगों को संबोधित करेगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा और साथ ही उपभोग और समग्र आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

GEO IAS
It's about quality

Page 04 : GS 2 : Indian Polity

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को पद की शपथ दिलाई।

- न्यायमूर्ति चंद्रन पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जो स्वीकृत पूर्ण संख्या से एक कम है।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति चंद्रन को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

Justice K. Vinod Chandran sworn in as SC judge; top court close to full strength

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Chief Justice of India Sanjiv Khanna administered the oath of office to the new Supreme Court judge Justice Krishnan Vinod Chandran on Thursday.

Justice Chandran was formerly the Chief Justice of the Patna High Court. His appointment has raised the judicial strength of the Supreme Court to 33, one short of the full sanctioned strength.

The Supreme Court Collegium had recommended Justice Chandran to the Union government for appointment as a top court judge on January 7.

Collegium resolution

In its resolution, the collegium headed by Chief Justice Khanna had noted that there was currently no judge with the Kerala High Court as the parent court on the Bench of the Supreme Court.

Justice K. Vinod Chandran

At the time of his recommendation, Justice Chandran was the senior-most among High Court judges hailing from Kerala. He had stood 13 in the combined all-India seniority of High Court judges.

Justice Chandran was appointed a judge of the Kerala High Court in November 2011 and elevated as the Patna High Court Chief Justice on March 24, 2023.

Justice Chandran is the second Supreme Court judge successfully recommended by the Khanna Collegium after Justice Manmohan in December 2024. His tenure in the top court would last till April 24, 2028.

Judicial vacancies

With pendency nearing 83,000, the Supreme Court Collegium has repeatedly emphasised the need to have its full sanctioned strength of judges.

A November 2023 collegium resolution had pointed out that the top court cannot afford even one judicial vacancy taking into account the "ever-mounting pendency of cases". The same sense of urgency was conveyed in a January 2024 resolution of the collegium, which said that the "workload of judges has increased considerably and it has become necessary to ensure that the court has full working judge-strength at all times".

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है?

- **सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति:**
- मूल रूप से, सर्वोच्च न्यायालय में आठ न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य) थे।\
- संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है।
- सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान शक्ति 34 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य) है।

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:

- संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि वह:
  - o व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - o कम से कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो ऐसे न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।
  - o वैकल्पिक रूप से, कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो।
  - o राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए।

नियुक्ति:

- संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
- राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियाँ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।

पद की शपथ:

- प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- शपथ में भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने और बिना किसी भय या पक्षपात के कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

कार्यकाल और त्यागपत्र:

- न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करता है।
- हालाँकि, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर 65 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले त्यागपत्र दे सकता है।

वेतन और भत्ते:

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर निर्भर करते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध:

- सेवानिवृत्ति के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत में किसी भी न्यायालय में कानून का अभ्यास करने या किसी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष दलील देने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वापस बुलाया जा सकता है।

हटाना:

- सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है।
- हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण की आवश्यकता होती है।
- हटाने का आधार सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता है।
- संसद के पास अभिभाषण प्रस्तुत करने और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने और उसे साबित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है।
- एक बार नियुक्त होने के बाद, न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं और सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता को छोड़कर अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें हटाया नहीं जा सकता।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली:

- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदोन्नति और स्थानांतरण पर निर्णय लेता है।
- "कॉलेजियम" शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है।

GEO IAS
It's about quality

In News : Phased Ceasefire in Gaza

- गाजा संघर्ष को संबोधित करने के उद्देश्य से कतर के दोहा में चरणबद्ध युद्धविराम समझौता किया गया।

समाचार का विश्लेषण:

- **चरणबद्ध युद्धविराम और बंदियों की अदला-बदली**
  - o पहले 42-दिवसीय चरण में, हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इज़राइल 900-1,650 फ़िलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा, जिनमें 7 अक्टूबर, 2023 के बाद हिरासत में लिए गए लोग भी शामिल हैं।
  - o यह चरण गाजा से अंततः इज़राइली वापसी के लिए आधार तैयार करता है, जिसमें नेटज़ारिम और फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो बाद की वार्ताओं पर निर्भर हैं।
  - o चरणबद्ध संरचना का उद्देश्य मानवीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विश्वास का निर्माण करना है।
- **भू-राजनीतिक और घरेलू बदलाव जो समझौते को सक्षम बनाते हैं**
  - o इज़राइल के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे कि गिदोन सा'आर नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल हो गए, ने दूर-दराज़ के लोगों के प्रभाव को कम कर दिया।
  - o अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से बिडेन और राष्ट्रपति-चुनाव ट्रम्प के तहत यू.एस. से, युद्धविराम को और आगे बढ़ाया।
  - o ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नेतन्याहू के रणनीतिक विचारों ने भी समझौते को स्वीकार करने के उनके निर्णय को प्रभावित किया।

मुख्य शब्द और निहितार्थ

- **फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वापसी:**
  - चरण एक के अंत तक इस महत्वपूर्ण बफर जोन को खाली करने की इजरायल की प्रतिबद्धता लंबे समय से चली आ रही मिस्र और हमास की मांगों को संबोधित करती है।
  - हालांकि, इजरायल के अधिकारी सतर्क बने हुए हैं, जिससे सुरक्षा चिंताओं के आधार पर फिर से बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है।

कैदी विनिमय गतिशीलता:

- इजरायल में उच्च-दांव वाले कैदी अदला-बदली का इतिहास फिर से सामने आया है, जिसमें कम से कम 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को रिहा किया जाना तय है। इस रियायत से राजनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम है, जो इस तरह के आदान-प्रदान को सीमित करने वाले इजरायल के 2014 के कानून को चुनौती देता है।

हमास और इजरायल के लिए निहितार्थ

- **हमास:**
- युद्ध विराम हमास को फिर से संगठित होने, अपने संसाधनों का पुनर्निर्माण करने और गाजा में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सांस लेने की जगह देता है। नेतृत्व के नुकसान के बावजूद इसकी विकसित रणनीति और स्थानीय कमांड की ताकत लचीलापन को उजागर करती है।
- हमास गाजा के शासन में एक स्थायी भूमिका के लिए खुद को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जो लेबनान के युद्ध-पश्चात ढांचे में हिजबुल्लाह के एकीकरण का अनुकरण करता है।

इजराइल:

- हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य सफलताओं के बावजूद, गाजा से हमास को खत्म करने का इजराइल का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जबकि यह समझौता बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करता है, नेतन्याहू कथित रियायतों के लिए घरेलू आलोचना का जोखिम उठाते हैं, जिससे संभावित रूप से उनका दूर-दराज़ समर्थन कमज़ोर हो सकता है।

निष्कर्ष: आगे एक जटिल रास्ता

- युद्धविराम हिंसा में एक अस्थायी विराम को दर्शाता है और गाजा में पुनर्निर्माण और शासन सहित व्यापक वार्ता के लिए रास्ते खोलता है।
- हालांकि, अनसुलझे सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियां इस समझौते की नाजुकता को उजागर करती हैं, जिससे क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता अनिश्चित हो जाती है।

गाजा पट्टी के बारे में

- **स्थान: यह भूमध्य सागर के तट पर एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है।**
  - यह इजरायल और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करता है।
  - पश्चिमी तट के साथ गाजा पट्टी फिलिस्तीन राज्य बनाती है। इन दोनों क्षेत्रों को इजरायल अलग करता है।
- प्रशासन: 2006 में बहुमत जीतने के बाद से, गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, जिसे एक राजनीतिक-सैन्य संगठन माना जाता है।
- कब्ज़ा: इजरायल गाजा और उसके तटरेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसने गाजा पट्टी में माल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। मिस्र भी गाजा की एक सीमा को नियंत्रित करता है और कई बार आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।
- संघर्ष: गाजा पट्टी को 'दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल' के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इजरायल ने अपने लगभग 2 मिलियन निवासियों पर सख्त आवाजाही प्रतिबंध लगा रखे हैं।

GEO IAS
It's about quality

An alliance of democracies with India at its core

Anders Fogh Rasmussen

served as North Atlantic Treaty Organization (NATO) Secretary General from 2009-14 and was the Prime Minister of Denmark from 2001-09

The year 2024 was the super-election year around the world, and 2025 must be the year when the world's democracies regroup and find new ways to support each other. Nowhere is this truer than in the relationship between Europe and India, a partnership that, for too long, has been big on strategies, but small on delivery. For nearly 17 years, European Union (EU)-India relations were seen through the prism of on/off Free Trade Agreement negotiations. As a free trader, I believe that the benefits of the world's biggest democracy and its largest trading bloc coming together to buck protectionist headwinds would be an economic and geopolitical game-changer.

Look at the bigger picture

However, we cannot be naive to the hurdles ahead. If a big-bang trade deal eludes us in the short term, we should develop another track away from the negotiators and bureaucrats. Fixed firmly at the highest political levels, it would focus on bigger picture geostrategic issues such as economic security, defence cooperation and a common agenda for space, emerging technology, and critical industry sectors such as pharmaceuticals.

On the geopolitical level, Europe was undoubtedly frustrated with India's response to Russia's invasion of Ukraine and continued close ties. These ties are historic. Conversely, India has broad rivalry with China, despite cooperation through the BRICS group and a substantial trading partnership. As a growing economy I can understand why India would not want to be sucked into power competition as the world divides into democratic and autocratic blocs. However, fundamentally, India is a democracy and its entanglement with Moscow and Beijing is unnatural. In the same vein, India's accusations of double standards from Europe are not without substance. We cannot demand that India severs all ties with Russia without also addressing our own economic dependence on China.

Europe and India need a more practical relationship; together, Europe, India and the United States can be unstoppable

A restart in relations should, therefore, start with a common assessment that Russia and China – with their 'No Limits' partnership – are both a threat to the global democratic world which includes India, Europe and the United States. What happens in the Atlantic affects the Indo-Pacific and vice versa.

On this basis we should focus on a series of practical measures to break down barriers to trade and investment piecemeal while strengthening our joint security, including economic security. This will include reducing dependencies on China in areas such as critical raw materials and developing new supply chains, with Europe seeing India as a 'Trusted Partner'.

Defence and trade

In defence, India and the U.S. already enjoy strong defence cooperation, with India being America's 'Major Defence Partner' and a member of the 'Quad' – sometimes referred to as the 'Asia-Pacific NATO'. Europe should support the continued development of this security alliance to give India more security guarantees.

EU-India defence discussions have increased but should accelerate to a high political level as Europe looks to bring much-needed investment into our industries, which can also offer India better weapons than Russia. The EU's new dedicated Defence Commissioner should visit India at the earliest opportunity and develop more collaboration, in defence and in space where both the EU and India have ambitious plans.

India and the EU have in place a Trade and Technology Council (TTC) to mirror a similar council with the Biden administration. Whether the EU-U.S. TTC survives President Donald Trump is unclear, but the EU-India Council has not reached its potential, especially in coordinating a technology agenda. Here, we can also draw inspiration from India's ties with the U.S., where the U.S.-India initiative on Critical and Emerging Technology (iCET); iCET is promoting collaboration at the National Security Adviser level.

The Australian Strategic Policy Institute illustrates the scale of the challenge. It tracks the top 64 emerging technologies. In 57 of them, China is winning the global race. The U.S. is hot on its heels. However, India is also emerging as a key centre of global research innovation, with many other European countries also still in the running. Individually, we are doing okay in this existential race, but by combining forces, the free world can jump ahead to lead the world in all emerging technology, from quantum computing to advanced biotech. We must not hand victory to China.

In perspective

Europe and India should focus on a far more practical relationship built on tangible connections, including stronger people-to-people ties. For Europe, the benefits are obvious: India will become the world's third largest economy in the next decade, at a time when European global GDP share continues to fall. But there is a wider prize: forming an alliance of democracies that has India at its core.

If Europe wants to anchor India in that alliance, we need to change our approach to the subcontinent. That does not mean brushing differences or difficulties under the table. India has many challenges to its democracy, but so does Europe. We should seek to address them together. Europe, India and the United States are individually powerful, but, together, we are unstoppable against the united autocrats.

GEO IAS
It's about quality

GS Paper 02 : अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: "जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में यूरोप और भारत के बीच संवर्धित सहयोग के दायरे और महत्व की जांच करें। इस साझेदारी को मजबूत करने के तरीके सुझाएं।" (**250 Words /15 marks)**

संदर्भ:

- लेख में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए यूरोप और भारत के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीतिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रूस और चीन जैसी निरंकुश शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की वकालत करता है।

एक लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करना

- वर्ष 2024 वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें सुपर-चुनाव की घटनाओं ने दुनिया के लोकतंत्रों को आकार दिया है। जैसे-जैसे 2025 सामने आता है, यह लोकतंत्रों के लिए फिर से संगठित होने और एक-दूसरे का समर्थन करने के नए तरीके बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- इन साझेदारियों में, यूरोप और भारत के बीच संबंध सबसे अलग हैं। रणनीतिक इरादे में ऐतिहासिक रूप से मजबूत होने के बावजूद, इसने प्रभावी वितरण के साथ संघर्ष किया है, और अब परिवर्तन का समय है।

यूरोपीय संघ-भारत संबंधों में चुनौतियाँ

- 17 से अधिक वर्षों से, यूरोपीय संघ-भारत संबंधों का ध्यान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता पर रहा है। इन लंबी चर्चाओं ने सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसके सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक के बीच एक सफल FTA, बढ़ते संरक्षणवादी रुझानों का मुकाबला करने और आर्थिक और भू-राजनीतिक ताकत को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला के रूप में काम कर सकता है। हालाँकि, वार्ता की जटिलता ने प्रगति में देरी की है, जिससे सहयोग के लिए एक व्यापक और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

व्यापार से आगे बढ़ना

- जबकि FTA महत्वपूर्ण बना हुआ है, व्यापार से परे भू-रणनीतिक मुद्दों की ओर बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें उच्च-स्तरीय राजनीतिक संवाद शामिल है, जो निम्न पर केंद्रित है:

- o लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा।
- o साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए रक्षा सहयोग
- o अंतरिक्ष अन्वेषण, उभरती प्रौद्योगिकियों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त नवाचार।

भू-राजनीतिक गतिशीलता और साझा चुनौतियाँ

- यूरोप और भारत जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता का सामना कर रहे हैं। यूरोप ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और मॉस्को के साथ उसके दीर्घकालिक संबंधों पर भारत की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की है।
- ये संबंध इतिहास में निहित हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत चीन के साथ अपनी जटिल प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाता है। ब्रिक्स के भीतर सहयोग के बावजूद, भारत बीजिंग के बढ़ते प्रभाव के बारे में सतर्क है, जो इसके व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संरेखित है।
- रूस और चीन दोनों के साथ भारत की भागीदारी, दुनिया के लोकतांत्रिक और निरंकुश गठबंधनों में ध्रुवीकृत होने के दौरान शक्ति ब्लॉकों में उलझने से बचने की इसकी रणनीतिक आवश्यकता को दर्शाती है। हालाँकि, चीन पर यूरोप की आर्थिक निर्भरता भी दोहरे मानदंडों को उजागर करती है।
- एक पारस्परिक समझ स्थापित की जानी चाहिए, यह पहचानते हुए कि रूस और चीन के बीच "कोई सीमा नहीं" साझेदारी लोकतांत्रिक दुनिया के लिए एक साझा खतरा है।

एक व्यावहारिक रूपरेखा का निर्माण

- इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए, व्यावहारिक कदमों की एक श्रृंखला को लागू किया जाना चाहिए:
  - o व्यापार और निवेश: बाधाओं को क्रमिक रूप से तोड़ना और महत्वपूर्ण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना।
  - o आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाकर चीन पर निर्भरता कम करें, जिसमें भारत को "विश्वसनीय भागीदार" के रूप में स्थापित किया जाए।
  - o रक्षा सहयोग: भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों को पूरक बनाने के लिए यूरोपीय संघ-भारत रक्षा चर्चाओं में तेजी लाना, सुरक्षा गारंटी को बढ़ाना।
  - o प्रौद्योगिकी नेतृत्व: चीन के वैश्विक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करें। रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना
- भारत का अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, इसके "प्रमुख रक्षा साझेदार" और क्वाड के सदस्य के रूप में, यूरोप के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- यूरोप द्वारा रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता को बदलने के लिए निवेश और उन्नत हथियारों की पेशकश के साथ यूरोपीय संघ-भारत रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।
- अंतरिक्ष अन्वेषण एक और आशाजनक क्षेत्र है जहाँ दोनों पक्ष आपसी लाभ के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ ला सकते हैं।
- प्रौद्योगिकी में, यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) अमेरिका के समान ढाँचे को दर्शाता है, फिर भी इसका कम उपयोग किया जाता है।

- यू.एस.-भारत iCET पहल से प्रेरणा लेते हुए, यूरोप और भारत चीन के प्रभुत्व द्वारा उत्पन्न अस्तित्वगत चुनौती का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं।

यूरोपीय संघ-भारत संबंधों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण

- आर्थिक और रणनीतिक संबंधों से परे, लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने से आपसी समझ गहरी हो सकती है।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान विश्वास और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

निष्कर्ष

- अगले दशक में, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जो यूरोप के लिए विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीतिक लक्ष्य लोकतंत्रों का एक मजबूत गठबंधन बनाना होना चाहिए, जिसमें भारत एक केंद्रीय स्तंभ हो। साझा चुनौतियों का समाधान करके, आपसी ताकतों को अपनाकर और ठोस सहयोग को बढ़ावा देकर, यूरोप, भारत और अमेरिका एक अजेय लोकतांत्रिक गठबंधन बना सकते हैं जो निरंकुश शक्तियों का मुकाबला करने और एक सुरक्षित, समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने में सक्षम हो।

GEO IAS
It's about quality